

# शिक्षा की भूमिका का मूल्यांकन: धालभूमगढ़ प्रखंड, झारखंड के आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण में

डॉ. राम कृष्ण पाल (Dr. Ram Krishna Paul)

व्याख्याता, स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान विभाग, घाटशिला कॉलेज घाटशिला, कोल्हान विश्वविद्यालय,  
चाईबासा, झारखंड, भारत

## सारांश

शिक्षा आदिवासी महिलाओं की सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, खासकर ऐसे क्षेत्रों में जैसे कि धालभूमगढ़ प्रखंड, झारखंड, जहां सामाजिक-आर्थिक चुनौतियां बनी रहती हैं। यह लेख आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण पर शिक्षा के बहुपहलू प्रभाव का अध्ययन करता है, जिसमें उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति, लिंग समानता, और निर्णय निर्माण प्रक्रियाओं में भागीदारी का प्रमुख ध्यान होता है। अमर्त्य सेन के प्राथमिक शिक्षा को विकास के लिए मूल स्तंभ के रूप में बताने के माध्यम से, लेख शिक्षा के महत्व को महत्वपूर्ण मानता है जो सरकारी जवाबदेही का मूल्यांकन करने और कौशल विकास को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण है। सरकारी प्रयासों के बावजूद, आदिवासी समुदाय, विशेष रूप से महिलाओं, गरीबी, अशिक्षा, और संदर्भानुरूप शिक्षण कार्यक्रमों की पहुँच की कमी जैसी बाधाएं आगे बनी रहती हैं। पुस्तक साहित्य की समीक्षा के माध्यम से, जैसे कि आदिवासी विकास, महिला शिक्षा, और आर्थिक सशक्तिकरण पर अध्ययन, लेख समस्याओं और संभावित समाधानों को उजागर करता है। सरकारी निजी संगठनों ने आदिवासी महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों को प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन समाज में अपार्थिवता और भेदभाव जैसी बाधाएं आगे बनी रहती हैं, जो उनकी भागीदारी को रोकती हैं।

मुख्य शब्द: शिक्षा, आदिवासी महिलाएँ, सशक्तिकरण, धालभूमगढ़ प्रखंड झारखंड, सामाजिक-आर्थिक विकास

## परिचय

शिक्षा का महत्व अनेक आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण कारक है, विशेष रूप से धालभूमगढ़ प्रखंड, झारखंड में। यहां के आदिवासी समुदायों में शिक्षा की उपलब्धता और स्तर को सुधारने से उन्हें सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक दृष्टिकोण से अधिक सक्रिय बनाया जा सकता है। शिक्षा के माध्यम से, आदिवासी महिलाएं अपने सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को समझती हैं और उन्हें सुधारने के लिए कदम उठाने में सक्षम होती हैं। शिक्षित महिलाएं अधिक जागरूक होती हैं और अपने अधिकारों को समझती हैं, जो उन्हें अपने समुदाय में सम्मान और स्थान प्राप्त करने में मदद करता है। शिक्षा की माध्यम से, आदिवासी महिलाएं अपने आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं और समुदाय के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान खोजने में सक्षम होती हैं। शिक्षा के माध्यम से उन्हें स्वास्थ्य, जल संरक्षण, और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझाया जा सकता है, जो उनके समुदाय के विकास में महत्वपूर्ण हैं। शिक्षा के माध्यम से, आदिवासी महिलाएं न केवल अपने व्यक्तिगत विकास में आगे बढ़ सकती हैं, बल्कि वे अपने समुदाय के विकास में भी

महत्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं। उन्हें नैतिक और सामाजिक मूल्यों का सम्मान करते हुए, वे अपने समुदाय के लिए नेतृत्व और प्रेरणा की भूमिका निभा सकती हैं।

इस तरह, शिक्षा न केवल आदिवासी महिलाओं के व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बल्कि उन्हें उनके समुदाय के साथ मिलकर उनके सामाजिक और आर्थिक स्तर को भी सुधारने में मदद करती है। इसलिए, धालभूमगढ़ प्रखंड और अन्य आदिवासी समुदायों में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो समुदाय के सभी सदस्यों के विकास में सहायक हो सकती है।

### भारत में शिक्षा: एक अवलोकन<sup>1</sup>

भारत, एक विविधताओं और संस्कृतियों का देश, अपनी शिक्षा प्रणाली के माध्यम से विभिन्न समाज और समुदायों को एक साथ लाने का प्रयास करता है। इस प्रयास का उद्देश्य न केवल शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को आदर्श नागरिक बनाना होता है, बल्कि इससे समाज का समृद्धि और विकास भी होता है। इस लेख में, हम भारतीय शिक्षा प्रणाली की संरचना पर ध्यान केंद्रित करेंगे और इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं को विस्तार से विश्लेषण करेंगे। भारत में शिक्षा प्रणाली की संरचना मुख्य रूप से तीन स्तरों पर आधारित है: प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा उन बच्चों के लिए है जो अभी तक शिक्षा के प्रारंभिक स्तर पर हैं। इसके बाद, माध्यमिक शिक्षा उन छात्रों के लिए है जो प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर चुके हैं, और उच्च शिक्षा विभिन्न विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए होती है।

प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों को बुनियादी शिक्षा प्रदान करना होता है। यह उन्हें आधारभूत गणित, भाषा, और विज्ञान की समझ प्राप्त कराता है, साथ ही उनके मानसिक, शारीरिक, और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा देता है। माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर, छात्रों को अधिक विस्तृत और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जाती है। इस स्तर पर, छात्रों को विभिन्न विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त करने का अवसर मिलता है जो उन्हें उनके कैरियर के लिए तैयार करता है। उच्च शिक्षा के स्तर पर, भारत में विभिन्न प्रकार की शिक्षा संस्थान हैं, जैसे विश्वविद्यालय, कॉलेज, और संस्थान। यहां विद्यार्थियों को विशेषज्ञता प्राप्त करने का मौका मिलता है, जो उन्हें उनके अनुसार कैरियर का चयन करने में मदद करता है।

भारत की शिक्षा में काफी प्रगति हुई है; उपलब्ध सबसे हाल के आंकड़ों के अनुसार, देश की साक्षरता दर धीरे-धीरे 74% से अधिक हो गई है। पुरुषों की साक्षरता दर महिलाओं की साक्षरता दर से अधिक है, जिससे लिंग समानता की समस्या का समाधान नहीं होता। लगभग 94% बच्चे आयु समूह 6 से 10 वर्ष के प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश करते हैं, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा के पहुँच को बढ़ाने के प्रयासों का परिणाम स्वरूप, जबकि लगभग 79% किशोर आयु समूह 11 से 18 वर्ष की उम्र में माध्यमिक शिक्षा में लगे हैं। 18 से 23 वर्ष के युवाओं का पोस्टसेकंडरी शिक्षा में प्रवेश भी बढ़ा है, जिनमें से लगभग 26% कॉलेज या विश्वविद्यालय में जाने का चुनाव करते हैं। शिक्षा क्षेत्र में निवेश करने पर सरकार का प्रतिबद्धता स्पष्ट है, जो शिक्षा पर खर्च को लगभग 3.8% जीडीपी के बराबर करती है। इसके अतिरिक्त, डिजिटल साक्षरता को आगे बढ़ाने के पहलों के परिणामस्वरूप, 40% जनसंख्या को अब मौलिक डिजिटल कौशल मौजूद है, जो शिक्षा में प्रौद्योगिकी की बढ़ती महत्ता को प्रकट करता है।

### शिक्षा और गरीबी : झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में<sup>2</sup>

भारत में झारखंड राज्य एक ऐसा क्षेत्र है जहां आदिवासी समुदायों का महत्वाकांक्षी शिक्षा और गरीबी के साथ सामना करना पड़ता है। झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की अन्यायपूर्णता और गरीबी के साथ

<sup>1</sup> भारत में शिक्षा का विकास: एक व्यापक अवलोकन | The Growth Of Education In India 2024 - The Knowledge Hub ([educationalvip.com](http://educationalvip.com))

<sup>2</sup> झारखंडी आदिवासियों का महामारी से सामना (in Hindi) - Vikalp Sangam

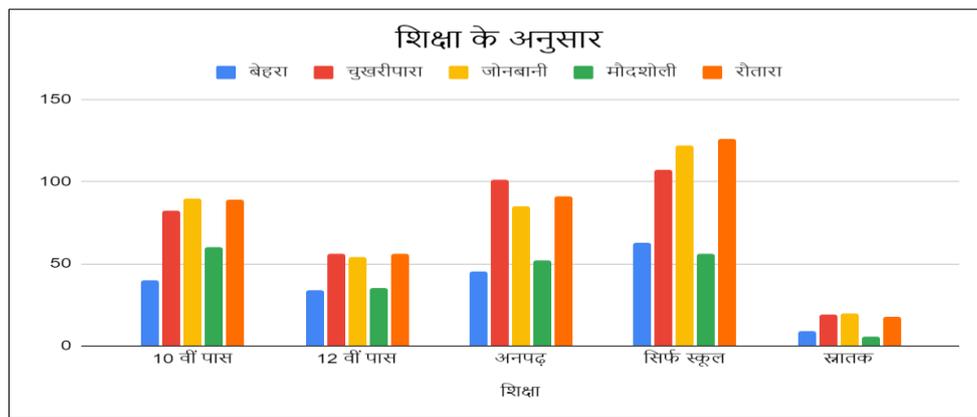
गहरा संबंध है। इन क्षेत्रों में शिक्षा की कमी, विद्यालयों की अधिकांशतः अवसादपूर्ण स्थिति, और शिक्षा संबंधी सुविधाओं की कमी आदिवासी समुदायों की गरीबी को और भी गहरा बना देती है। झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर मध्यम तक ही होता है, जो कि आदिवासी युवाओं के करियर और विकास को प्रभावित करता है। शिक्षा की कमी के कारण, युवा आदिवासी अक्सर बेरोजगारी और गरीबी के चक्र में फंस जाते हैं। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों ने विभिन्न योजनाओं को शुरू किया है। इनमें शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, शिक्षा संबंधी सुविधाओं का विस्तार, और आदिवासी समुदायों को शिक्षित और सक्षम बनाने के लिए कई योजनाएं शामिल हैं। इस प्रकार, झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के माध्यम से गरीबी को कम करने के लिए कई पहल की जा रही हैं। यह एक लम्बा सफर है, लेकिन इसके प्रयासों से आदिवासी समुदायों के उत्थान और विकास में मदद मिल सकती है।

तालिका विभिन्न गांवों में व्यक्तियों द्वारा प्राप्त शिक्षा के स्तर को दर्शाती है। डेटा को पांच श्रेणियों में बांटा गया है :10वीं पास, 12वीं पास, निरक्षर, केवल स्कूली शिक्षा और स्नातक। इन पाँच गांवों में जोनबानी में सबसे ज्यादा 10वीं पास) 90) लोग हैं, जबकि बेहरा में सबसे कम) 40) हैं। इसी तरह, में 12वीं पास करने वालों की संख्या चुखरीपारा और रौतारा में) 56) है, जबकि बेहरा में सबसे कम) 34) हैं। निरक्षरता के मामले में, बेहरा में सबसे कम निरक्षर व्यक्ति) 45) हैं, जबकि चुखरीपारा में सबसे अधिक) 101) हैं। जब एकमात्र स्कूली शिक्षा श्रेणी की बात आती है, तो रौतारा में व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक) 126) है, और मौदाशोली में सबसे कम) 56) है। मौदाशोली में सबसे कम ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने स्नातक की डिग्री) 06) प्राप्त की है, जबकि जोनबानी में सबसे अधिक) 20) हैं।

आंकड़े बताते हैं कि जहां इन गांवों में 10वीं कक्षा तक शिक्षा पूरी करने वाले व्यक्तियों की संख्या काफी अधिक है, वहीं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले या उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या कम है। डेटा इन ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

शिक्षा	गांव का नाम					
	बेहरा	चुखरीपारा	जोनबानी	मौदाशोली	रौतारा	कुल योग
10वीं पास	40	82	90	60	89	361
12 वीं पास	34	56	54	35	56	235
अनपढ़	45	101	85	52	91	374
सिर्फ स्कूल	63	107	122	56	126	474
स्नातक	9	19	20	6	18	72
कुल योग	191	365	371	209	380	1516

स्रोत: - लेखक द्वारा उत्पन्न



स्रोत: - लेखक द्वारा उत्पन्न

आदिवासियों की शिक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, न केवल यह तथ्य को ध्यान में लेते हुए कि सरकार और नीति निर्माताओं ने इन्हें पिछले में समान अवसर नहीं दिए थे, बल्कि यह उनके समुदाय और राष्ट्र के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। झारखंड में कई अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चे, आदिवासी बच्चों की तरह, गरीबी, अशिक्षा और वंचितता के एक बीचस्थी पीढ़ी के फंसे हुए हैं। यह स्पष्ट है कि बहुत ही कम आदिवासी समुदायों के बच्चों में उत्कृष्ट वयस्क अशिक्षा दर है, जो कि अत्यंत गरीब वयस्क साक्षरता दरों का पुनः उत्पन्न करती है। हालांकि सरकार ने आदिवासी कल्याण और शिक्षा के लिए विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों की शुरुआत की है, हालात में बहुत कम उन्हें आदिवासी तक पहुँचाया गया है और उनका फायदा हुआ है। इनमें से कई कार्यक्रम आदिवासी समुदाय को इसलिए लाभ नहीं पहुंचा क्योंकि इन कार्यक्रमों को क्षेत्रीय, भौगोलिक और शारीरिक अंतरों और बाधाओं को ध्यान में रखकर सांगठनिक किया और स्थानीय बनाया नहीं गया था। एक और कारण था/है कि कार्यक्रमों के लाभ आदिवासियों तक नहीं पहुंचे थे/पहुंच रहे हैं वह राजनीतिक इच्छा की कमी, भ्रष्टाचार, और आदिवासी क्षेत्र में विकास पर कम ध्यान दिया गया है। भारतीय संविधान ने आदिवासियों को विशेष स्थान प्रदान किया है। परंपरागत रूप से उन्हें आदिवासी, वनवासी, जनजातियां, या आदिवासियों के रूप में जाना जाता है। भारत में आदिवासी जनसंख्या 74.6 मिलियन है। झारखंड राज्य में 6.6 मिलियन आदिवासी जनसंख्या है। झारखंड राज्य में तीन दशकों के 30 विभिन्न आदिवासी समुदाय निवास करते हैं और वे राज्य की जनसंख्या का 26.3 प्रतिशत हैं। इनमें से साठ प्रतिशत से अधिक आदिवासियों को गरीबी रेखा के नीचे जीना पड़ता है।

धालभूमगढ़ प्रखंड, झारखंड में शिक्षा का महत्व आदिवासी महिलाओं को सशक्त बनाने में क्रियाशील है, जिसका कई महत्वपूर्ण आंकड़े प्रमाणित करते हैं। 45% से दस साल पहले तुलना में, क्षेत्र की आदिवासी महिलाओं की साक्षरता दर में व्यापक वृद्धि हुई है, अब यह लगभग 65% है। उसी तरह, प्राथमिक विद्यालयों में दाखिले लेने वाली लड़कियों का प्रतिशत बढ़ा है, जो पिछले 60% से लगभग 80% तक है। इसके अलावा, उच्चतर माध्यमिक और सीनियर सेकेंडरी शिक्षा पूरी करने वाली आदिवासी महिलाओं का प्रतिशत 25% से अब 40% से अधिक हो गया है। पेशेवर प्रशिक्षण के कार्यक्रमों का भी महत्वपूर्ण प्रभाव हुआ है; लगभग आधे आदिवासी महिलाओं को कौशल-आधारित प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है, जिससे उनकी रोजगार क्षमता में सुधार हुआ है। इसके परिणामस्वरूप, करीब 55% तक पहुँचे शिक्षित महिलाओं का व्यावसायिक श्रमिकों में भर्ती होने का अनुपात बढ़ा है। इसके अतिरिक्त, निर्णय-लेने की स्वतंत्रता और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे सशक्तिकरण के सूचकों में प्रगति हुई है; लगभग 70% शिक्षित आदिवासी महिलाएँ स्वास्थ्य सुविधाओं और निर्णय अधिकार में अधिक पहुँच के बारे में रिपोर्ट करती हैं। ये आंकड़े धालभूमगढ़ प्रखंड, झारखंड में आदिवासी महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास और सामान्य कल्याण पर शिक्षा के सकारात्मक प्रभाव को प्रकट करते हैं।

**उद्देश्य धालभूमगढ़ प्रखंड , झारखंड**

धालभूमगढ़ प्रखंड, झारखंड में आदिवासी महिलाओं को सशक्तिकरण में शिक्षा की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना, जिसमें उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को मजबूत करने, जेंडर समानता को बढ़ावा देने, और उनकी समुदायों में निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित है।

### साहित्य की समीक्षा

[1] **सिंधी, एस. (2012).** झारखंड के धालभूमगढ़ प्रखंड में आदिवासी विकास एक प्रमुख सफलता कहानी को दर्शाता है, जहां पहले से ही अत्याचारित समुदाय अब शिक्षा में उत्थान और सुधारी हुई जीवन गुणवत्ता का साक्षात्कार कर रहे हैं। जबकि सरकारी प्रयासों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) का योगदान आदिवासी जनसंख्या के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण और विकास के अवसर प्रदान करने में समान रूप से महत्वपूर्ण है। एआरटी इंटरनेशनल परियोजना के रूप में, एआरटी इंडिया समूह ने दूरस्थ आदिवासी गांवों के निवासियों के लिए महत्वपूर्ण ज्ञान और कौशल प्राप्ति के रास्ते को खोजने के लिए एक सर्वेक्षण किया। परियोजना, विशेष रूप से महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करके, आदिवासी समुदायों की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण पहलों की महत्वपूर्णता पर जोर देता है। यह लेख झारखंड के धालभूमगढ़ प्रखंड में आदिवासी महिलाओं के बीच प्रशिक्षण और कौशल विकास के प्रयासों में प्रवेश करता है। यह विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किए जाने वाले यातना के मामलों, शारीरिक और मानसिक हिंसा के मामलों, और समाज में पूर्वाग्रह के मामलों सहित की सामना करने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। इन अवरोधों के बावजूद, सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा की जा रही प्रयासों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में है। लेख उन अविशिष्ट महिलाओं की सफलता की कहानियों पर प्रकाश डालता है जिन्होंने शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अपने आप को सशक्त किया है। इसके अलावा, यह धालभूमगढ़ प्रखंड, झारखंड में आदिवासी महिलाओं की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित व्यावसायिक और कौशल आधारित प्रशिक्षण पहलों की समीक्षा करता है, जैसे कि कृषि वनस्पति, पापड़ बनाना, सिलाई, पकाना, और सेनेटरी पैड उत्पादन।

[2] **कपूर, आर. (2023).** आदिवासी महिलाओं की शिक्षा। आदिवासी समुदायों से संबंधित महिलाएं शिक्षा का मतलब और महत्व स्वीकार कर चुकी हैं। वे उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त करने, रोजगार के अवसरों में लगने, अपनी जीवन की शर्तों को योग्य ढंग से बनाए रखने और अपने संपूर्ण जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने की इच्छा रखती हैं। आदिवासी समुदायों में, शिक्षा की प्रणाली एक अच्छे विकसित स्थिति में नहीं है। शिक्षा के प्रणाली में, कई क्षेत्र हैं, जिनमें कमी है। उनमें सुधार लाने के लिए उपाय और कार्यक्रमों को तैयार किया जाना चाहिए। आदिवासी महिलाएं शिक्षा प्राप्ति के कार्य के दौरान कई समस्याओं का सामना करती हैं। इनमें से एक प्रमुख समस्या है कि कुछ मामलों में, वे अपने परिवार के सदस्यों से समर्थन और सहायता प्राप्त नहीं करती हैं। इसके अतिरिक्त, आदिवासी व्यक्तियों के पास गरीबी और पिछड़ापन की स्थिति में निवास है। इसलिए, आदिवासी महिलाओं को शिक्षा प्राप्ति के कार्य के दौरान कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इससे उनकी संपूर्ण जीवन शर्तों का समृद्धि में सहायता होती है। लेकिन वर्तमान में, आदिवासी व्यक्तियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हो रहा है और वे अपनी लड़कियों को शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसलिए, आदिवासी महिलाओं के बीच शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है और शिक्षा प्रणाली के संपूर्ण सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है। इस अनुसंधान पेपर में लिए गए मुख्य अवधारणाएं हैं, आदिवासी महिलाओं की शिक्षा प्राप्ति में आने वाली समस्याएं और आदिवासी महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यों को लागू करने के उपाय।

[3] **भुव्या, डी. (2014).** आंध्र प्रदेश में शिक्षा के माध्यम से आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण। शिक्षा महिलाओं को ज्ञान, कौशल, और स्वायत्तता प्राप्त कराने के सबसे महत्वपूर्ण साधनों में से एक है, जो

विकास प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लेने के लिए आवश्यक है। यह उच्च उत्पादकता, दक्षता और बेहतर सामाजिक-आर्थिक विकास की ओर ले जाता है। सहभागी लोकतंत्र और आर्थिक स्वतंत्रता सशक्तिकरण के मुख्य तत्व हैं। शिक्षा के माध्यम से अत्याचारित आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण राष्ट्रीय विकास में बहुत योगदान करेगा। सशक्तिकरण की दिशा में कदम रखना आदिवासी महिलाओं के लिए एक दूरस्थ सपना है। आदिवासी महिलाओं की शैक्षिक स्थिति उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में बहुत कम है। महिलाओं की शिक्षा को एक राष्ट्र के विकास में सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक माना जाता है। आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण वर्तमान स्थिति में एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा है। बिना आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण के, देश के मानवधिकार का सच्चा और समय संवेदनशील विकास संभव नहीं है। आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण उनके पास आर्थिक संसाधनों पर आय कमाने और उनकी प्रति-व्यक्ति आय, शिक्षा के लिए पहुंच, पेशेवर अवसरों की पहुंच और आर्थिक निर्णय लेने में उनकी शक्ति के माध्यम से मापा जा सकता है, और उनकी राजनीतिक अवसरों के प्राप्ति के माध्यम से। आदिवासी महिलाओं का शिक्षा एक साधन है जो अत्याचारित आदिवासी महिलाओं के बीच शक्तिशाली बनाता है। आंध्र प्रदेश में 35 आदिवासी समुदाय रह रहे हैं जिनका विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि है। अंत में, लेख एक शैक्षिक नीति की मांग को लेकर समाप्त होता है जो आंध्र प्रदेश में आवश्यक शिक्षा का उत्तरदायित्व संपूर्णतः उठाए।

[4] सिंह, के. (2016). भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण में शिक्षा का महत्व। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा: "अगर आप किसी व्यक्ति को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, हालांकि, अगर आप किसी महिला को शिक्षित करते हैं तो आप पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। महिलाएँ सशक्त होती हैं तो माँ भारत सशक्त होता है।" जब लगभग आधे जनसंख्या का योगदान देने वाली महिलाएँ सशक्त होती हैं तो यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। महिलाओं को शिक्षित करना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक मील का पत्थर माना जाता है क्योंकि यह उन्हें चुनौतियों का सामना करने, उनके पारंपरिक भूमिका का सामना करने और अपने जीवन को बदलने की क्षमता प्रदान करता है। शिक्षा का पहुंच बढ़ाने के बावजूद, भारत में लिंग भेदभाव अभी भी बना रहता है और महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में अधिक कुछ किया जाना चाहिए। महिलाओं में बहुत सारी अनअनुसंधानित संभावनाएँ हैं जिन्हें कभी भी नहीं खोजा गया है। क्योंकि शिक्षा न केवल मानव विकास का एक प्रविष्टि है बल्कि एक उपयुक्त और उद्यमी विकास का एक प्रविष्टि है, शिक्षात्मक समानता सक्षम और उद्यमी विकास सुनिश्चित करेगी। आज, लिटरेसी दर 2011 जनगणना के अनुसार महिलाओं की 65.46% है जबकि पुरुष लिटरेसी दर 80% से अधिक है। लिटरेसी से आगे, शिक्षा महिलाओं के अधिकारों, मर्यादा और सुरक्षा के लिए बहुत कुछ कर सकती है। शिक्षा विकास के लिए स्वतंत्रता के स्वर्ण दरवाजे को खोलने की कुंजी है। इलीन मैलोन बीच शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, और आय को एक आशीर्वादित त्रिमूर्ति मानती हैं क्योंकि वे इतने करीबी रिश्तेदार हैं। यह लेख शिक्षा के प्रभाव पर महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में चर्चा करता है साथ ही उन चुनौतियों और परिवर्तनों के बारे में भी जो उन्हें सामना करना पड़ता है।

[5] ऐंड, टी., & ओराओं, एस. (2013). झारखंड में जनजातीय महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। जनजातीय समाज में महिलाएं अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के तरीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और अपने समाज में आर्थिक संपदा के रूप में मानी जाती हैं। लेकिन वे अभी भी विभिन्न जीवन के क्षेत्रों में पिछड़ गई हैं जैसे शिक्षा, रोजगार, अच्छे स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तिकरण आदि। सशक्तिकरण को कमजोर वर्गों, खासकर जनजातीय महिलाओं को शक्ति और संसाधनों का अधिग्रहण और अधिकार करने की समझा जा सकता है, ताकि वे अपने निर्णय ले सकें। डेटा और फील्ड अवलोकन के विश्लेषण के बाद, यह प्रकट होता है कि शिक्षा की कमी, खराब स्वास्थ्य स्थिति और शिशु मृत्यु दर, कम वेतन

के काम की स्तर, स्व-रोजगार के अवसर की कमी, संगठन क्षमता और नेतृत्व क्षमता जनजातीय महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की मुख्य बाधाओं में हैं। सरकार और गैर-सरकारी संगठनों को जनजातीय महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उपयुक्त योजनाएँ और कार्यक्रम तैयार करने चाहिए।

[6] **काकाटी, बी. के., & काकोटी, एस. (2022).** महिला सहकारी के रोल में महिलाओं की सशक्तिकरण में: झारखंड में एक अध्ययन। महिला सशक्तिकरण का प्रश्न कई नांसानुसार होता है। हालांकि, प्राथमिक दृष्टिकोण आत्म-सशक्तिकरण का रहता है, फिर भी स्व-अस्तित्व की प्रक्रिया बड़े पैमाने पर समाजीय बलों और कारकों के जटिल प्रभावों के कई अन्य कारकों पर निर्भर करती है। झारखंड, भारत के राज्य में जनजातीय महिलाओं का अध्ययन, महिला-नेतृत्व वाले सहकारी समाज के दृष्टिकोण से किया गया है जो मुर्गी पालन के माध्यम से अपने सदस्यों को अधिक आय प्रदान करने का प्रयास करता है, वह महिला सदस्यों के बीच अंतर्व्यक्तिक संबंध और आत्मसम्मान में पश्चिमोत्तर परिवर्तनों का रोचक झलक प्रदान करता है।

[7] **पल्ली, आर., देब, ए., & भद्रा, प. (2020).** एसएचजीएस से महिला सशक्तिकरण: झारखंड के जनजाति गाँवों से चिमटी रोशनी। 'महिला सशक्तिकरण' अब सामाजिक वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण विचार का विषय हो गया है। 'सशक्तिकरण' का अवधारणा पहले राजनीतिज्ञों ने हाइलाइट किया था। बिना संदेह, मानव संभावनाओं का प्रभावी उपयोग और उसके बारे में ज्ञान का अनुभव व्यक्तियों की सबसे महत्वपूर्ण क्षमताएँ मानी जाती हैं। शायद यही 'सशक्तिकरण' की जड़ है। शब्द 'महिला सशक्तिकरण' महिलाओं के अपने संभावनाओं के बारे में जागरूकता को प्रतिनिधित्व करता है। दूसरी ओर, एसएचजीएस दृष्टिकोण समूह द्वारा महिलाओं के संभावनाओं को खोलने की दिशा में होता है, जो उन्हें उनकी खुद की क्षमता से अपनी सहायता करने की क्षमता प्रदान करता है। इसके बावजूद, महिला एसएचजीएस की स्थिति खतरे में है। यह समूचा स्थिति को सामान्यीकृत करना काफी कठिन हो सकता है। इसलिए नहीं कि एसएचजीएस सहनी नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्योंकि विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों के अनुसार विभिन्न सफलता कहानियाँ हैं। अध्ययन एक नम्र प्रयास है जो झारखंड के देवघर और पूर्व सिंघभूम जिलों के महिला एसएचजीएस (एनजीओ द्वारा विकसित) को दोबारा देखने का प्रयास करता है। जनजाति सामाजिक-आर्थिक जीवन के कई कारकों में से एक फैमिली आधारित खेती, महत्वपूर्ण विशेषता लिंग भूमिका है। लगभग सभी जीवन के क्षेत्रों में जनजाति महिलाएं घरेलू और आर्थिक क्षेत्र में जिम्मेदारियों को साझा कर रही हैं। अध्ययन एक एक्स-पोस्ट फैक्टो अनुसंधान डिज़ाइन पर आधारित है। डेटा संग्रह के तरीके रांगीन और गुणात्मक प्रकृति के थे और कुछ शोध प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए उद्देश्य रखे गए थे। सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन और एफजीडी शासकीय विधाओं के महत्वपूर्ण तरीके हैं।

[8] **नारायण, बी., & चक्रवर्ती, यू. के. (2019).** झारखंड में अनुसूचित जनजातियों के बीच शिक्षा का सामग्री विश्लेषण। यह पेपर भारत के झारखंड राज्य में जनजातियों के शैक्षिक स्थिति का सामग्री विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह जनजातियों के बीच अक्षरता दरों, जातिवार शैक्षिक स्थिति को उजागर करता है, और प्रत्येक श्रेणी में लिंग, जनजातियों और ग्रामीण-शहरी विभाजन के अक्षरता की गड़बड़ी को दर्शाता है। यह उन्हीं चयनित राज्यों में जनजातियों के शैक्षिक स्थिति की तुलना भी करता है। पेपर में भारत सरकार और झारखंड सरकार द्वारा शैक्षिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में लागू योजनाओं और कार्यक्रमों की विविध योजनाओं की रिपोर्ट की गई है। मुख्य रूप से, पेपर शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप और उपलब्धि का विवेचन करता है और एक संदर्भ में झारखंड की जनजातियों के साथ सर्वसाधारण प्रारंभिक शिक्षा की प्राप्ति की दिशा को समझने का प्रयास करता है।

[9] **भास्कर, पी., & कौशिक, म. (2022).** जनजातियों द्वारा सहकारिता आधारित उद्यमों में महिला नेतृत्व के प्रवृत्तियां - झारखंड में सहकारिता आधारित जनजातियों के उद्यमों में एक अध्ययन। यह पेपर झारखंड, भारत में सहकारिता के माध्यम से महिला उद्यमिता पहलों की स्थिति का विश्लेषण करने का प्रयास करता है और जनजातियों की महिलाओं के सशक्तिकरण पर प्रभाव और उनके आर्थिक योगदान पर उनके नेतृत्व क्षमताओं को हाइलाइट करता है। एशियाई समाजों के सभी क्षेत्रों में महिला नेतृत्व पदों के लिए मोलभाव की मांग महत्वपूर्ण होती जा रही है, जबकि जनजातियों के विकास को अधिकतर सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी के रूप में सीमित रहने के लिए रह गया है। 21वीं सदी में जनजातियों से महिला नेताओं की मान्यता अब भी एक दूरदर्शी सपना है। हालांकि, झारखंड के जनजातियों में आर्थिक सशक्तिकरण और समूह गतिविधियों ने उनकी नेतृत्व क्षमताओं को परिवर्तित करने में बड़ा योगदान किया है और उनकी नेतृत्व क्षमताओं को परिवर्तित करने में उनका अब भारी समर्थन है। पेपर क्षेत्र में केस स्टडीज, द्वितीयक डेटा और साहित्य समीक्षा के आधार पर लेखक के अध्ययन के परिणामों को साझा करता है, जो जनजातियों की महिलाओं के नेतृत्व में प्रवृत्तियों के संबंध में संबंधित है। अध्ययन दिखाता है कि झारखंड के जनजातियों की महिलाएं परंपरागत रूप से सामाजिक रूप से असशक्त हैं और उन्हें सामाजिक रूप से असशक्त माना जाता है और उन्हें सामाजिक नेतृत्व पदों से अधिकतर बाहर रखा जाता है। यह भी प्रकट करता है कि संचालन और समर्थन के साथ, वे सफल संगठित उद्यमों को प्रबंधित करने के लिए उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमताओं का प्रदर्शन करती हैं।

[10] **एक्का, बी. ए., & प्रसाद, ए. (2007).** जनजातीय झारखंड में शिक्षा और गरीबी: एक स्थितिकी विश्लेषण। यह पेपर 'जनजातीय झारखंड में शिक्षा और गरीबी' के बीच संबंधों का परीक्षण करने का प्रयास करता है। पेपर को तीन खंडों में विभाजित किया गया है। खंड I शिक्षा संस्थानों की मानव संसाधन विकास में भूमिका पर चर्चा करता है। इसमें समस्या के सिद्धांतिक पहलुओं पर चर्चा की गई है और शिक्षा और गरीबी के बीच विभिन्न संबंधों का वर्णन किया गया है। खंड II विशेष रूप से झारखंड में शिक्षा और इसके समाज में जीवन पर प्रभाव का विश्लेषण करता है, विशेष रूप से वंचित और जनजातियों के बारे में। और खंड III में लेखक सारांश प्रदान करते हैं, झारखंड में शैक्षिक संस्थानों द्वारा किए गए प्रमुख खोज की समस्याओं का सारांश, और इन्हें हल करने के सुझाव।

[11] **जाधव, वि., & पिराबु, जे. वी. (2019).** एकाशस्त्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र की भूमिका में स्वायत्त सहायता समूह जनजाति किसान महिलाओं की आजीविका सुरक्षा को मजबूत करने में। कृषि विज्ञान केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की योजनाबद्ध योजना ने खेती के वृद्धि, खाद्य सुरक्षा, आजीविका सुरक्षा आदि के क्षेत्र में महिलाओं को उनके सशक्तिकरण के लिए ज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुगमन के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कृषि विज्ञान केंद्र स्वयं सहायता समूह के गठन और कार्यकर्ता द्वारा उद्यमीकरण प्रशिक्षण पर जोर देता है जो उन्हें आत्मविश्वास, दृष्टिकोण, प्रेरणा, आर्थिक स्वतंत्रता, निर्णय निर्माण, नेतृत्व, सामाजिक गतिशीलता आदि विकसित करने में मदद करता है। इसलिए, इस अध्ययन के माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका को समझने का प्रयास किया गया है, स्वायत्त सहायता समूह जनजाति किसान महिलाओं के उद्यमी गतिविधियों के माध्यम से उनकी आजीविका सुरक्षा को मजबूत करने में। वर्तमान अध्ययन को महाराष्ट्र राज्य के जनजातियों द्वारा प्रभावित जिला पालघर में परिपत्रिक रूप से चयनित किया गया था। कुल दो ब्लॉक चयनित किए गए, प्रत्येक ब्लॉक में पांच गांव यादृच्छिक रूप से चयनित किए गए थे जहां कृषि विज्ञान केंद्र ने स्वायत्त सहायता समूह जनजाति किसान महिलाओं को प्रशिक्षण दिया था। इस प्रकार, कुल 10 गांव चयनित किए गए और प्रत्येक चयनित गांव से 20 प्रतिस्पर्धियों का चयन किया गया। इस प्रकार, कुल 200 को अध्ययन के लिए चयनित किया गया। शैक्षिक स्वायत्त समूह जनजाति किसान महिलाओं

की आजीविका सुरक्षा को मापने के लिए, एक सूचकांक (इकबाल, 2015) द्वारा विकसित किया गया सूचकांक का उपयोग किया गया।

[12] देवान, आर. (2010). महिलाओं की स्थिति: जनजातीय महिलाओं के सशक्तिकरण पर एक अनुभवात्मक अध्ययन। यह पेपर जनजातीय महिला - पुरुष सेकेंडरी स्कूल के छात्रों (कक्षा-X) के नारी सशक्तिकरण के प्रति रुचि की जाँच करता है। स्टैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग द्वारा प्राप्त डेटा जनजातीयता (जनजातीय और अजनजातीय), लिंग (पुरुष और महिला) और सामाजिक-आर्थिक स्थिति (उच्च और निम्न) के दो उप-समूहों पर आधारित था। झारखंड के रांची जिले में स्थित विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों से 320 छात्रों का नमूना निकाला गया था। महिला सामाजिक स्वतंत्रता स्केल (डब्ल्यू.एस.एफ.एस.) का उपयोग नमूने की महिला सशक्तिकरण के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन करने के लिए किया गया था (भूषण, 1987) और मानसिक स्वास्थ्य को मापने के लिए जीएचक्यू - 12 का उपयोग किया गया था। परिणाम दिखाते हैं कि उच्च सामाजिक-आर्थिक स्तर के पुरुष-महिला स्कूली छात्रों के नमूने के नारी सशक्तिकरण और मानसिक स्वास्थ्य की दिशा में प्रतिशत मूल्य निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर के नमूने समूह से अधिक पाए गए। जनजातीय नमूने में पुरुष और महिला दोनों का नारी सशक्तिकरण और मानसिक स्वास्थ्य की दिशा में अधिक प्रवृत्त होने का पता चला था, तुलनात्मक समूह से।

संदर्भ	मुख्य फोकस	मुख्य नतीजे/सफारिशें
[1] आदिवासी विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का महत्व	सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के योगदान, महिलाओं के बीच प्रशिक्षण और कौशल विकास	आदिवासी समुदायों के लिए विकास कार्यक्रमों का संचालन, आर्थिक सहायता, और सामाजिक सशक्तिकरण
[2] आदिवासी महिलाओं की शिक्षा और समस्याएं	शिक्षा प्राप्ति में सामने आने वाली समस्याएं, परिवार से समर्थन की कमी, आर्थिक संबंधित समस्याएं	आदिवासी महिलाओं के लिए शिक्षा का पहुंच, सामाजिक परिवार समर्थन की वृद्धि, और आर्थिक सहायता
[3] आंध्र प्रदेश में आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण	शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण, आदिवासी महिलाओं के शैक्षिक स्थिति का विश्लेषण	आदिवासी महिलाओं के लिए शैक्षिक योजनाओं की पुनरारंभ, सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन, और समाज में उनके योगदान को समझने की वृद्धि
[4] सिंह, के. (2016). भारत में	महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शिक्षा का महत्व, लिंग	शिक्षा के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण,

महिलाओं के सशक्तिकरण में शिक्षा का महत्व	भेदभाव की समस्या, सामाजिक और आर्थिक समानता	लिंग भेदभाव के खिलाफ उत्साहित करना, सामाजिक और आर्थिक समानता की बढ़ावा देना
[5] ऐंड, टी., & ओराओं, एस. (2013). झारखंड में जनजातीय महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण।	जनजातियों की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, शिक्षा की अभाव, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव	जनजातियों की महिलाओं के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ाना, सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए नीतियों और कार्यक्रमों का विकास
[6] काकाटी, बी. के., & काकोटी, एस. (2022). महिला सहकारी के रोल में महिलाओं की सशक्तिकरण में: झारखंड में एक अध्ययन।	महिला सहकारिता के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण, आर्थिक संबंधों का महत्व, जनजाति महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास में सहायक	महिला सहकारिता के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण, जनजाति महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सहायक योजनाओं का विकास
[7] पल्ली, आर., देब, ए., & भद्रा, प. (2020). एसएचजीएस से महिला सशक्तिकरण: झारखंड के जनजाति गाँवों से चिमटी रोशनी।	महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण, संगठनित रूप से योजनाओं का महत्व, आर्थिक स्वतंत्रता के लिए उत्तेजना	महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए संगठित योजनाओं का महत्व, आर्थिक स्वतंत्रता के लिए उत्तेजना और सामाजिक अनुसंधान का महत्व
[8] नारायण, बी., & चक्रवर्ती, यू. के. (2019)	झारखंड में अनुसूचित जनजातियों के बीच शिक्षा का सामग्री विश्लेषण	जनजातियों के शैक्षिक स्थिति का विश्लेषण, जातिवार शैक्षिक स्थिति को उजागर करना, लिंग, जनजातियों और

		ग्रामीण-शहरी विभाजन के अक्षरता की गड़बड़ी को दर्शाना।
[9] भास्कर, पी., & कौशिक, म. (2022)	झारखंड में सहकारिता आधारित जनजातियों के उद्यमों में महिला नेतृत्व के प्रवृत्तियां	महिलाओं के सशक्तिकरण पर प्रभाव और उनके आर्थिक योगदान पर उनके नेतृत्व क्षमताओं को हाइलाइट करना।
[10] एक्का, बी. ए., & प्रसाद, ए. (2007)	जनजातीय झारखंड में शिक्षा और गरीबी: एक स्थितिकी विश्लेषण	शिक्षा और गरीबी के बीच संबंधों का परीक्षण, जनजातियों की महिलाओं के नेतृत्व में प्रवृत्तियों के संबंध में संबंधित है।
[11] जाधव, वि., & पिराबु, जे. वी. (2019)	स्वायत्त सहायता समूह जनजाति किसान महिलाओं की आजीविका सुरक्षा	कृषि विज्ञान केंद्र और स्वायत्त सहायता समूह की भूमिका, महिलाओं के उद्यमी गतिविधियों के माध्यम से आजीविका सुरक्षा को मजबूत करने में।
[12] देवान, आर. (2010)	जनजातीय महिलाओं के सशक्तिकरण	महिला सशक्तिकरण की जाँच, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग और उपयोगिता के उपाय।

### निष्कर्ष

संदर्भों को समझने और समझौता करने के लिए झारखंड में शिक्षा प्रणाली के संदर्भ और पृष्ठभूमि को समझने की अत्यधिक आवश्यकता है ताकि जनजातियों को शिक्षा के बराबर पहुंच प्रदान करने का सवाल संबोधित किया जा सके। राज्य में जनजातियों को ऐतिहासिक रूप से संसाधनों और अवसरों की पहुंच से वंचित किया गया है। सरकार के वर्तमान प्रयास इन बच्चों को स्वीकृत स्कूलों में लाने और उन्हें अच्छी गुणवत्ता के कार्यात्मक स्कूल प्रदान करने में दोहराई नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे, जब भी जनजाति के बच्चे स्कूलों में दाखिल होते हैं, तो शिक्षा प्रणाली उन्हें सम्मान और गरिमा के साथ उपचार करने के लिए बहुत कुछ नहीं करती है, इसके बजाय, जनजाति के बच्चों को एक अपमानजनक और अपमानजनक माहौल के साथ सम्मिलित किया जाता है जो निरंतर भेदभाव और

अलगाव करता है। ऐसे ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों के लिए, शिक्षा की पहुंच प्रदान करना बस काफी नहीं है, सरकार को उनके संक्षिप्त और अक्षरहीनता की पीढ़ी को नष्ट करने और उसे उन्नति और अक्षरहीनता के इंटरजेनरेशनल साइकिल को तोड़ने की सामान्य शर्तों और अवसरों को बनाने में प्रोएक्टिव भूमिका निभानी चाहिए। एक संवेदनशील शिक्षकों और ब्यूरोक्रेसी का तंत्र निश्चित रूप से अंतर करने के लिए आवश्यक है।

## संदर्भ

1. सिंधी, एस. (2012). जनजातीय महिलाओं के सशक्तिकरण में संभावनाएँ और चुनौतियाँ। आईओएसआर मानविकी और सामाजिक विज्ञान पत्रिका, 6(1), 46-54।
2. कपूर, आर. (2023). जनजातीय महिलाओं की शिक्षा। अंतर्राष्ट्रीय सूचना, व्यवसाय और प्रबंधन पत्रिका, 15(3), 96-104।
3. भुक्पा, डी. (2014). आंध्र प्रदेश में शिक्षा के माध्यम से जनजातीय महिलाओं का सशक्तिकरण। अभिनव प्रौद्योगिकी और अनुकूल प्रबंधन की अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका, 1(5), 116-119।
4. सिंह, के. (2016). भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण में शिक्षा का महत्व। मदरहुड अंतर्राष्ट्रीय बहुविज्ञानीय अनुसंधान और विकास पत्रिका, 1(1), 39-48।
5. ऐंड, टी., & ओराओं, एस. (2013). झारखंड में जनजातीय महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण - एक विश्लेषण। अनुसंधानिका, 5(1/2), 85।
6. काकाटी, बी. के., & काकोती, एस. (2022). महिला सहकारी समितियों की भूमिका में महिलाओं की सशक्तिकरण: झारखंड में एक अध्ययन। पुरुषार्थ - प्रबंधन, नैतिकता और आध्यात्मिकता की एक पत्रिका, 15(1), 118-132।
7. पल्ली, आर., देब, ए., & भद्रा, प. (2020). एसएचजी द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण: झारखंड के आदिवासी गांवों से उजागर दिशाएँ। संपादकीय बोर्ड, 9(4), 186।
8. नारायण, बी., & चक्रवर्ती, यू. के. (2019). झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा का सामग्री विश्लेषण: सरकार के दृष्टिकोण और सजगता को जोर देते हुए। जनजातीय अध्ययनों में दृष्टिकोण का परिवर्तन: एक मानवविज्ञानीय दृष्टिकोण से अन्यविद्या और संरक्षण, 203-231।
9. भास्कर, पी., & कौशिक, एम. (2022). झारखंड, भारत में सहकारी आधारित जनजातियों के उद्यमों में महिलाओं के नेतृत्व के चलन: अध्ययन। अंतरराष्ट्रीय बहुविद्यालय: अनुप्रयोगिक व्यावसायिक और शिक्षा अनुसंधान, 3(1), 19-30।
10. एक्का, बी. ए., & प्रसाद, ए. (2007). झारखंड की जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा और गरीबी: स्थितिका विश्लेषण। झारखंड विकास और प्रबंधन अध्ययन, 5(3), 2471-2482।
11. जाधव, वी., & पिरबू, जे. वी. (2019). पालघर जिले, भारत में स्व-सहायता समूह जनजातीय खेतीकर महिलाओं की आजीविका सुरक्षा को मजबूत करने में केकेवी की भूमिका। अंतर्राष्ट्रीय वर्तमान माइक्रोबायोलॉजी और अनुप्रयोगिक विज्ञान, 8(8), 1151-1157।
12. देवान, आर. (2010). महिलाओं की स्थिति: जनजातीय महिलाओं के सशक्तिकरण पर एक औद्योगिक अध्ययन। सामाजिक आधुनिकता, 22।